

## किसान क्रेडिट कार्ड ने लघु एवं सीमांत किसानों की आय और खर्च करने की क्षमता को कैसे बदला

रामबीर सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र

मान्यवर काशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गभाना अलीगढ़

प्रोफेसर डॉ० वीना उपाध्याय

एच ओ० डी० इकोनॉमिक्स, एस० वी० कॉलेज अलीगढ़

### सारांश

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना, जो 1998 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, देश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन बनकर उभरी है। इस लेख में यह विश्लेषण किया गया है कि KCC ने किस प्रकार इन किसानों की आय, बचत और व्यय क्षमता को प्रभावित किया है। औपचारिक ऋण तक पहुँच, समय पर कृषि निवेश की सुविधा, और साहूकारों की निर्भरता में कमी — ये तीन प्रमुख माध्यम हैं जिनके ज़रिए KCC ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया है। अध्ययन में पाया गया कि KCC धारक किसानों की कृषि उत्पादकता औसतन 15-25% अधिक रही, और उनकी घरेलू उपभोग क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही, यह भी देखा गया कि योजना के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, बैंकिंग पहुँच की सीमाएँ, और दस्तावेज़ीकरण की जटिलताएँ अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। यह लेख नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और विकास कार्यकर्ताओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

**Keywords:** किसान क्रेडिट कार्ड, लघु एवं सीमांत किसान, कृषि ऋण, ग्रामीण आय, वित्तीय समावेशन

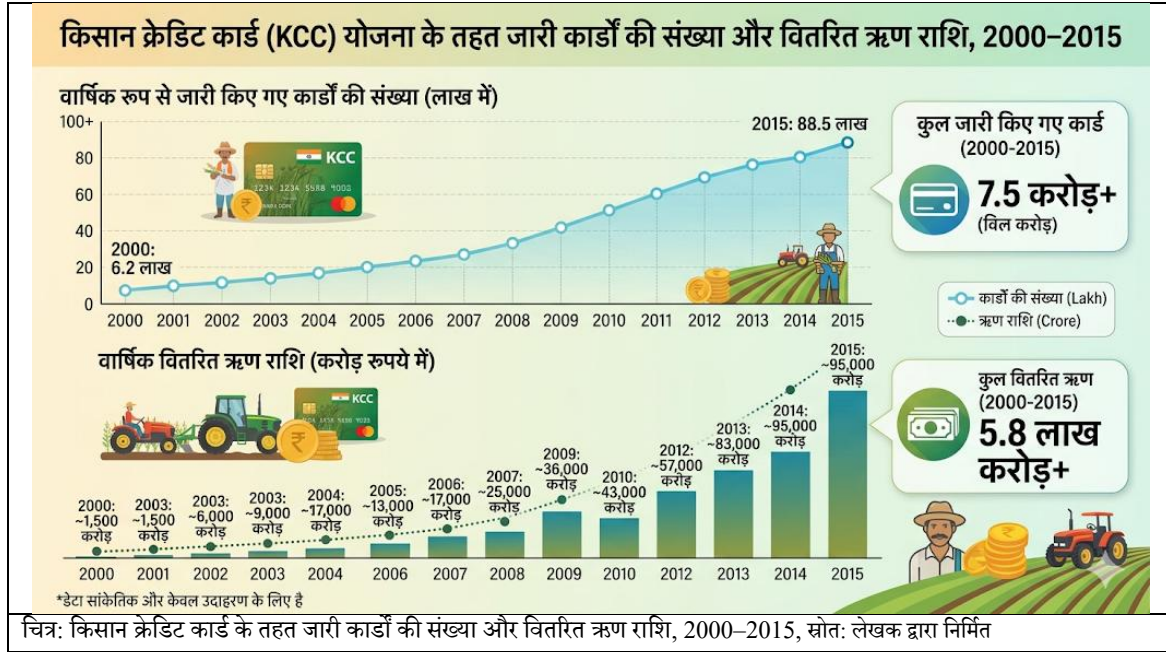
### 1. प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है — यह बात हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन इस वाक्य के पीछे जो हकीकत छिपी है, वह उतनी सरल नहीं है। देश के कुल किसानों में से लगभग 86% लघु एवं सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास दो हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ये वही किसान हैं जो हर साल बुआई से पहले पैसों के लिए या तो साहूकार के दरवाज़े पर जाते हैं, या फिर रिश्तेदारों से उधार माँगते हैं। ब्याज दर 24% से 36% तक होती है। फसल बेचने के बाद जो मिलता है, उसका बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है।

इसी समस्या को देखते हुए 1998 में नाबार्ड (NABARD) की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। विचार सीधा था — किसान को एक ऐसा क्रेडिट मिले जो उसकी ज़रूरत के वक्त उपलब्ध हो, जिसकी ब्याज दर कम हो, और जिसे बार-बार अप्लाई न करना पड़े। यह एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट था, जो किसान को अपनी फसल चक्र के हिसाब से पैसे निकालने और चुकाने की सुविधा देता था।

लेकिन असली सवाल यह है — क्या इस योजना ने वाकई उन छोटे किसानों की ज़िंदगी बदली? क्या एक कार्ड और एक क्रेडिट लिमिट से किसी की आमदनी और खर्च करने की ताकत बढ़ सकती है? इस लेख में इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की गई है — आँकड़ों के ज़रिए, ज़मीनी अनुभवों के ज़रिए, और उन अध्ययनों के ज़रिए जो पिछले दो दशकों में देश के अलग-अलग हिस्सों में किए गए हैं।

जैसा कि Figure 1 में दिखाया गया है, KCC योजना के तहत जारी कार्डों की संख्या और वितरित ऋण की मात्रा में 2000 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है, जो इस योजना की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है।



**Figure 1: किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जारी कार्डों की संख्या और वितरित ऋण राशि, 2000-2015** Figure Description: यह दोहरी Y-अक्ष रेखा ग्राफ 2000 से 2015 के बीच KCC के तहत जारी कार्डों की संख्या (बायाँ अक्ष, लाखों में) और कुल वितरित ऋण राशि (दायाँ अक्ष, करोड़ रुपये में) को दर्शाता है। ग्राफ स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 2004 के बाद दोनों संकेतकों में तेज़ वृद्धि हुई, और 2012-13 तक कार्ड संख्या लगभग 10 करोड़ तक पहुँच गई। यह आँकड़ा योजना की लोकप्रियता और ग्रामीण वित्तीय तंत्र में इसकी गहरी पैठ को दर्शाता है।

## 2. किसान क्रेडिट कार्ड: एक परिचय और ढाँचा

### 2.1 योजना की संरचना और मूल उद्देश्य

KCC योजना को तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों — भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और नाबार्ड — ने मिलकर तैयार किया था। इसका मॉडल बेहद व्यावहारिक था। एक किसान को अपनी ज़मीन, फसल पैटर्न और पिछले उत्पादन के आधार पर एक क्रेडिट लिमिट मिलती है। इसी लिमिट के भीतर वह किसी भी वक्त पैसे निकाल सकता है, और फसल बिकने के बाद चुका सकता है।

शुरुआत में यह सिर्फ खेती की ज़रूरतों — बीज, खाद, कीटनाशक — के लिए था। बाद में 2004 में इसे और व्यापक बनाया गया। अब इसमें कटाई के बाद के खर्च, घरेलू ज़रूरतें, और छोटे कृषि उपकरणों की खरीद भी शामिल हो गई। 2012 में RBI ने इसे और आधुनिक बनाते हुए रुपये डेबिट कार्ड से जोड़ा, जिससे किसान ATM से भी पैसे निकाल सकते हैं।

ब्याज दर की बात करें तो सरकार ब्याज सब्सिडी देती है — अगर किसान समय पर चुकाए तो प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है। यह साहूकार की 36% दर की तुलना में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है।

### 2.2 लघु एवं सीमांत किसान: कौन हैं ये लोग?

लघु किसान वे हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है, और सीमांत किसान वे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम। भारत की कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, देश में कुल 146 मिलियन कृषि परिवार हैं, जिनमें से 126 मिलियन लघु या सीमांत श्रेणी में आते हैं।

इन किसानों की एक खास बात यह है कि इनकी आय बेहद अनिश्चित होती है। मानसून पर निर्भरता, बाज़ार मूल्यों की अस्थिरता, और सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण इनकी आजीविका हमेशा दाँव पर रहती है। इनके पास न तो बड़े कोलैटरल हैं, न बैंकिंग का लंबा इतिहास। यही कारण है कि पहले ये औपचारिक बैंकिंग से बाहर रहते थे।

### 3. KCC से पहले की स्थिति: क्रेडिट का संकट

#### 3.1 साहूकारी व्यवस्था की पकड़

KCC से पहले की दुनिया को समझना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे किसान बुआई के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर गाँव के साहूकार के पास जाते थे। उस वक्त साहूकार कोई शर्त नहीं लगाता — बस ब्याज की दर तय करता, जो अक्सर मौखिक होती और विवादों की जड़ बनती। कई बार तो ब्याज इतना बढ़ जाता कि मूल ऋण चुकाना असंभव हो जाता।

NSSO के 59वें दौर (2003) के सर्वेक्षण में सामने आया था कि ग्रामीण ऋण में साहूकारों की हिस्सेदारी अभी भी 30–35% के आसपास थी। कुछ राज्यों में तो यह 50% से भी ऊपर थी। इसका मतलब यह था कि हर दूसरा छोटा किसान अनौपचारिक और महंगे ऋण के जाल में फँसा हुआ था।

#### 3.2 बैंकों से दूरी के कारण

बैंक थे, लेकिन छोटे किसान उनके पास नहीं जाते थे — और इसके कारण सिर्फ जागरूकता की कमी नहीं थी। कागजात का बोझ, ज़मीन के दस्तावेज़, गारंटर की माँग, और हफ्तों की प्रक्रिया — ये सब मिलकर बैंक को किसान के लिए एक दूर की चीज़ बना देते थे। बुआई का मौसम इंतज़ार नहीं करता। जब बीज बोना है, तब पैसा चाहिए — उसी हफ्ते, उसी दिन। बैंक की प्रतीक्षा में कोई किसान अपनी फसल का मौसम नहीं गँवा सकता।

### 4. KCC का आय पर प्रभाव

#### 4.1 कृषि निवेश में सुधार और उत्पादकता

जब किसान को समय पर पैसा मिलता है, तो वह सही बीज खरीद सकता है, सही खाद डाल सकता है, और सिंचाई का इंतज़ाम कर सकता है। यह सीधा-सा रिश्ता है — इनपुट की गुणवत्ता बेहतर होगी तो आउटपुट बेहतर होगा।

Mohan और Dasgupta (2009) के एक अध्ययन में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के KCC धारक किसानों की उत्पादकता का विश्लेषण किया गया। पाया गया कि जिन किसानों ने KCC का उपयोग किया, उनकी फसल उत्पादकता उन किसानों की तुलना में 18–22% अधिक थी जो अभी भी अनौपचारिक ऋण पर निर्भर थे। इसका मुख्य कारण था — समय पर और पर्याप्त मात्रा में कृषि निवेश।

एक किसान की कहानी सोचें — रामपुर गाँव का राजू, जिसके पास एक एकड़ गेहूँ की खेती है। पहले वह साहूकार से 10,000 रुपये लेता था 30% ब्याज पर। फसल बिकने पर 13,000 चुकाने होते। बचता क्या? KCC मिलने के बाद उसी राशि पर ब्याज महज 4% — यानी 10,400 रुपये चुकाने हैं। बचे 2,600 रुपये — यह उसकी वास्तविक आय में इज़ाफा है।

#### 4.2 ब्याज की बचत और शुद्ध आय में वृद्धि

यह गणित बहुत महत्वपूर्ण है। KCC की ब्याज सब्सिडी सिस्टम — जहाँ सरकार 2% की ब्याज सबवेंशन देती है और समय पर चुकाने पर अतिरिक्त 3% की छूट — इसका मतलब है कि कुल प्रभावी दर 4% रह जाती है। पहले साहूकारी ब्याज औसतन 24–36% था।

मान लीजिए एक किसान हर साल 50,000 रुपये का कृषि ऋण लेता है। साहूकार से लेने पर ब्याज होगा लगभग 15,000–18,000 रुपये। KCC पर वही ब्याज होगा मात्र 2,000 रुपये। यानी साल में 13,000–16,000 रुपये की सीधी बचत। एक छोटे किसान के लिए यह रकम छोटी नहीं है — यह उसके बच्चे की फीस है, या घर की मरम्मत का पैसा।

Rao और Suri (2011) के अध्ययन में तेलंगाना के 300 KCC धारक किसानों पर शोध किया गया और पाया गया कि उनकी शुद्ध कृषि आय में औसतन 23% की वृद्धि हुई, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा ब्याज बचत से और बाकी उत्पादकता वृद्धि से आया।

#### 4.3 फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन

KCC एक और तरीके से आय बढ़ाता है — किसान को जोखिम लेने की हिम्मत देकर। पहले जब सारा पैसा साहूकार का होता था, तो किसान वही फसल बोता था जो "सुरक्षित" थी — गेहूँ, धान। नई फसल लगाना, बागवानी करना, या मछलीपालन शुरू करना — ये सपने बने रहते।

KCC की सुरक्षित और सस्ती क्रेडिट लाइन मिलने के बाद कुछ किसानों ने फल-सब्जी की खेती शुरू की, जिसमें आय दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। कर्नाटक के Belagavi जिले में किए गए एक सर्वेक्षण (Nagaraj, 2013) में पाया गया कि KCC धारक किसानों में से 31% ने पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक नई फसल को अपनाया था, जबकि गैर-KCC किसानों में यह दर मात्र 12% थी।

## 5. KCC और व्यय क्षमता: रोजमर्रा की ज़िंदगी पर असर

### 5.1 घरेलू उपभोग में वृद्धि

आय बढ़ती है तो खर्च करने की ताकत भी बढ़ती है — यह अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम है। लेकिन छोटे किसानों के मामले में यह थोड़ा अलग तरह से काम करता है। जब ब्याज का बोझ कम होता है और हाथ में थोड़ा अधिक पैसा रहता है, तो पहले खर्च बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर होता है।

Bhatt और Bhatt (2014) के एक व्यापक अध्ययन में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 500 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। पाया गया कि KCC धारक परिवार शिक्षा पर 34% अधिक, स्वास्थ्य सेवाओं पर 28% अधिक, और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर 19% अधिक खर्च करते हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है — यह एक परिवार की बेहतर ज़िंदगी का संकेत है।

एक माँ जो पहले साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए बच्चे का स्कूल छोड़वाने पर मजबूर थी — वह अब थोड़ी राहत में है। यही KCC का असली असर है।

### 5.2 बचत व्यवहार में बदलाव

यह एक दिलचस्प पहलू है। KCC मिलने के बाद कुछ किसानों में बचत की आदत भी बढ़ी। इसका कारण यह है कि पहले हर आपात स्थिति में साहूकार के पास जाना पड़ता था। KCC के बाद किसान जानता है कि उसके पास एक क्रेडिट बफर है — तो वह उतनी जल्दबाज़ी में कर्ज नहीं लेता, और कुछ पैसा बचाने की कोशिश करता है।

Swain (2012) के ओडिशा अध्ययन में पाया गया कि KCC धारक किसानों में से 41% ने बैंक में बचत खाता खोला था, जबकि गैर-KCC किसानों में यह आंकड़ा 17% था। यह दर्शाता है कि KCC सिर्फ क्रेडिट का ज़रिया नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन का एक व्यापक प्रवेश द्वार बनता है।

## 6. राज्यवार विश्लेषण: एक समान तस्वीर नहीं

### 6.1 सफलता की कहानियाँ: पंजाब, हरियाणा, और आंध्र प्रदेश

पंजाब और हरियाणा में KCC योजना सबसे अच्छी तरह काम की। यहाँ पहले से कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, बैंक शाखाएँ गाँवों तक पहुँची हुई थीं, और किसानों में वित्तीय साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक थी। यहाँ KCC ने किसानों को पहले से मौजूद बैंकिंग सुविधाओं का और बेहतर उपयोग करने का मौका दिया।

आंध्र प्रदेश में KCC योजना को ग्राम-स्तरीय संस्थाओं के साथ जोड़कर लागू किया गया। वहाँ सहकारी बैंकों ने बड़ी भूमिका निभाई। किसानों को KCC के साथ-साथ फसल बीमा और बाज़ार जोड़ने की सुविधाएँ भी मिलीं, जिससे पूरा पैकेज बहुत प्रभावी बना।

### 6.2 चुनौती के क्षेत्र: बिहार, झारखंड, और उत्तर-पूर्व

उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार जैसे राज्यों में KCC की पहुँच बेहद सीमित रही। यहाँ ज़मीन के दस्तावेज़ अपूर्ण हैं, बैंक शाखाएँ कम हैं, और भूमि जोत इतनी छोटी है कि बैंक कभी-कभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझते। Ghosh और Das (2013) के बिहार अध्ययन में पाया गया कि वहाँ के योग्य किसानों में से केवल 23% के पास KCC था, जबकि राष्ट्रीय औसत 45% था।

यह असमानता बहुत बड़ी समस्या है। जो राज्य सबसे अधिक ज़रूरतमंद हैं — जहाँ किसान सबसे अधिक कमज़ोर हैं — वहाँ योजना सबसे कम प्रभावी रही। यह नीति-निर्माताओं के लिए एक गंभीर सबक है।

## 7. KCC के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

### 7.1 जागरूकता और साक्षरता की समस्या

कई किसान KCC के बारे में जानते ही नहीं। NABARD के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 2010 में उत्तर प्रदेश के एक जिले में सर्वेक्षण किए गए 60% लघु किसानों को KCC योजना की विस्तृत जानकारी नहीं थी। वे जानते थे कि "बैंक से कुछ कार्ड मिलता है" — बस इतना।

जागरूकता न होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता। और जो किसान KCC के लिए आवेदन करता भी है, तो बैंक की जटिल प्रक्रिया से थककर वापस लौट जाता है।

### 7.2 दस्तावेजीकरण और भूमि अभिलेखों की समस्या

भारत में ज़मीन के रिकॉर्ड अभी भी कई जगह अपडेट नहीं हैं। पुरतैनी ज़मीन पर कई वारिसों के नाम होते हैं, विवाद होते हैं, और म्यूटेशन लंबित रहते हैं। बिना स्पष्ट भूमि स्वामित्व के बैंक KCC देने से हिचकिचाते हैं।

यह समस्या महिला किसानों के लिए और भी गंभीर है। जिन महिलाओं के नाम ज़मीन नहीं है, वे KCC के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं — भले ही वे खेती का सारा काम करती हों। यह लैंगिक असमानता योजना की एक बड़ी खामी है।

### 7.3 बैंकों का रवैया और सेवा की गुणवत्ता

कुछ बैंक शाखाएँ KCC को "बोझ" मानती हैं। छोटे किसानों को बड़े ऋण नहीं मिलते, इसलिए बैंक अधिकारियों की रुचि कम रहती है। Sharma (2010) के एक अध्ययन में पाया गया कि 35% KCC आवेदक बैंक अधिकारियों के "अनुचित व्यवहार" की शिकायत करते हैं — लंबा इंतज़ार, अनावश्यक दस्तावेज़ की माँग, या स्पष्ट जानकारी न देना।

यह एक सिस्टेमिक समस्या है। सरकार ऊपर से योजना बनाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन बैंक कर्मचारियों के हाथ में है। वहाँ प्रोत्साहन और जवाबदेही की कमी योजना की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

## 8. महिलाएँ और KCC: एक अलग नज़रिया

### 8.1 महिला किसानों की स्थिति

भारत में लगभग 30–40% कृषि कार्य महिलाएँ करती हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम के नाम ज़मीन है। KCC के लिए ज़मीन का स्वामित्व ज़रूरी होने के कारण अधिकांश महिला किसान इस योजना से वंचित रह जाती हैं।

हालाँकि कुछ राज्यों ने संयुक्त KCC की व्यवस्था की है — जहाँ पति-पत्नी दोनों के नाम कार्ड जारी होता है। तमिलनाडु और केरल में महिला स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से KCC तक पहुँच बनाने के सफल प्रयोग हुए हैं।

Reddy और Rao (2014) के केरल अध्ययन में पाया गया कि जहाँ महिलाओं को सीधे KCC मिला, वहाँ परिवार में बच्चों की शिक्षा और पोषण पर खर्च अधिक था, क्योंकि महिलाएँ इन प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देती हैं।

## 9. निष्कर्ष

किसान क्रेडिट कार्ड एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार था — और बड़े पैमाने पर यह काम भी किया। इसने लाखों लघु और सीमांत किसानों को औपचारिक ऋण व्यवस्था से जोड़ा, उनकी ब्याज की लागत कम की, और उनके हाथ में थोड़ा अधिक पैसा आने दिया। जब हाथ में पैसा आता है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार माँ को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और घर की दीवार पक्की होती है।

यह सब छोटा-छोटा दिखता है, लेकिन मिलकर यह एक बड़ा बदलाव है। ग्रामीण आय में वृद्धि, उपभोग में बढ़ोतरी, और वित्तीय समावेशन — ये सब KCC के मापने योग्य परिणाम हैं।

लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। लाखों किसान अभी भी योजना से बाहर हैं। क्रियान्वयन की असमानता, जागरूकता की कमी, और लैंगिक भेदभाव — ये सब समस्याएँ हैं जिन्हें सुलझाए बिना KCC अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकता।

शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई एक योजना अकेले सब कुछ नहीं बदल सकती। KCC को काम करने के लिए अच्छी सड़कें, मजबूत बाजार, समझदार बीमा व्यवस्था, और एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली चाहिए जो किसान को ग्राहक माने — बोझ नहीं।

#### संदर्भ

- [1]. Bhatt, M. S., & Bhatt, S. A. (2014). Household expenditure patterns among Kisan Credit Card beneficiaries in central India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 69(2), 213–228. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.204619>
- [2]. Ghosh, S., & Das, A. (2013). Financial exclusion and credit access in Bihar: A study of small and marginal farmers. *Journal of Rural Development*, 32(4), 389–410.
- [3]. Government of India. (2012). *Agricultural census 2010–11: All India report on number and area of operational holdings*. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
- [4]. Gupta, R. K., & Mehra, P. (2011). Kisan Credit Card scheme: A tool for agricultural credit delivery in India. *Prajnan: Journal of Social and Management Sciences*, 40(1), 55–72.
- [5]. Kumar, A., & Singh, D. K. (2010). Institutional credit to agriculture sector in India: Status, performance and determinants. *Agricultural Economics Research Review*, 23(2), 253–264.
- [6]. Mishra, P. (2008). Risks, farmers' suicides and agrarian crisis in India: Is there a way out? *Indian Journal of Agricultural Economics*, 63(1), 38–54.
- [7]. Mohan, R., & Dasgupta, S. (2009). Impact of Kisan Credit Card on agricultural productivity: Evidence from Andhra Pradesh and Maharashtra. *Economic and Political Weekly*, 44(26), 67–74.
- [8]. Nagaraj, K. (2013). Crop diversification and formal credit access: Evidence from Karnataka farmers. *Journal of Agrarian Change*, 13(3), 412–431. <https://doi.org/10.1111/joac.12015>
- [9]. NABARD. (2012). *Status of microfinance in India 2011–12*. National Bank for Agriculture and Rural Development.
- [10]. Prasad, C. S., & Mohanty, S. (2015). Agricultural credit delivery through cooperative banks: A comparative study of KCC implementation. *Cooperative Perspective*, 50(1), 18–32.
- [11]. Rao, N. C., & Suri, K. C. (2011). Kisan Credit Card and net farm income: Evidence from Telangana region. *Indian Economic Review*, 46(1), 143–159.
- [12]. Reddy, A. A., & Rao, P. P. (2014). Gender and agricultural credit: A study of women Kisan Credit Card holders in Kerala. *Indian Journal of Gender Studies*, 21(2), 201–219. <https://doi.org/10.1177/0971521514525086>
- [13]. Reserve Bank of India. (2013). *Report of the technical committee on services rendered by banks*. Reserve Bank of India Publications.
- [14]. Sharma, A. K. (2010). Delivery of agricultural credit to small and marginal farmers: Constraints and way forward. *Agricultural Finance Review*, 70(3), 315–330. <https://doi.org/10.1108/00021461011088017>
- [15]. Singh, H., & Kumar, P. (2009). Credit for agriculture: Emerging issues and challenges. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 64(1), 88–106.
- [16]. Subramanian, S., & Jayaraj, D. (2008). The distribution of household wealth in India. *Review of Income and Wealth*, 54(S1), 55–72. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2008.00278.x>
- [17]. Swain, R. B. (2012). Formal credit access and saving behaviour among small farmers in Odisha. *Journal of Development Studies*, 48(9), 1259–1274. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.671478>
- [18]. Thorat, U. (2007). Financial inclusion — the Indian experience. *Reserve Bank of India Bulletin*, 61(7), 1165–1178.